राजा उर्फ राजिंदर

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 486/2010)

अप्रैल 10, 2015

[दीपक मिश्रा और एन.वी. रमन्ना, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस.302, 201 परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि- माना गया: साक्ष्य उचित संदेह से परे साबित हुआ कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था- चाकू, खून से सने कपड़े और पीड़ित के जले हुए कंबल की राख की बरामदगी- मृतक आरोपी-अपीलकर्ता के कहने पर किया गया था- सबूतों से पता चला कि आरोपी-अपीलकर्ता को मृतक के अपनी पत्नी के साथ संबंध के बारे में संदेह था- इस मकसद (मोटिव) ने अभियोजन पक्ष के मामले को भी मजबूत किया- दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया गया :-

1. अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर था। अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ यह थीं कि मृतक घटना की तारीख पर शाम के शुरुआती समय में आरोपी-अपीलकर्ता के साथ उसके घर से बुलाया गया था। इसके बाद, अपीलकर्ता को मृतक के साथ चाय की दुकान पर देखा गया। मृतक के भाई, पीडब्लू-8 ने गवाही दी कि उसने आरोपी से ठिकाने के संबंध में पूछताछ की थी। मृतक के बारे में, क्योंकि मृतक आरोपी के साथ गया था और उस समय आरोपी ने जवाब दिया था कि चाय की दुकान पर एक सिख लड़का आया था और मृतक उसके

साथ गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक और आरोपी सह-ग्रामीण थे। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में, आरोपी-अपीलकर्ता ने मृतक के साथ जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उक्त साक्ष्यों के संचयी अध्ययन और उचित मूल्यांकन से यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था। दूसरी परिस्थिति चाकू, खून से सने कपड़े और जले हुए कंबल की राख की बरामदगी को लेकर थी. जब्ती के गवाह पीडब्लू-7 और पीडब्लू-9 ने जब्ती को साबित कर दिया। खून से सने कपड़े और हथियार चाकू को फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला भेज दिया गया। हालाँकि, ब्लड ग्रुप का कोई मिलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कपड़े और चाकू पर मानव खून कैसे लगा। डॉक्टर पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से राय दी कि मृतक के शरीर पर चोटें चाकू के कारण हो सकती हैं और उक्त राय का खंडन नहीं किया गया था। दूसरी परिस्थिति यह थी कि पीडब्लू-7, एक टैक्सी ड्राइवर, ने गवाही दी थी कि उस दिन जब वह यात्रियों को लेने के लिए फतेहाबाद जा रहा था, तो उसने देखा कि आरोपी के घर के सामने एक बैलगाड़ी खड़ी थी और कुछ लोग एक गठरी बांध रहे थे। एक "पल्ली" में. उसके पूछताछ करने पर आरोपियों ने उसे बताया कि वे खेतों में खाद ले जा रहे हैं। हालाँकि, इस गवाह ने अतिशयोक्तिपूर्ण बयान दिया और गिरफ्तारी के समय के बारे में अलग-अलग बताया, फिर भी इस आशय की उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसने आरोपी को एक विशेष स्थान पर "पल्ली" में एक बंडल के साथ देखा था। कहावत "फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ऑम्निबस", भारत में लागू नहीं है। कोर्ट को झूठ को सत्य से अलग करने का हर संभव प्रयास करें, और यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए, जब अनाज को भूसी से अलग करना पूरी तरह से असंभव हो, क्योंकि वे इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि ऐसे गवाह के पूरे साक्ष्य की आवश्यकता होती

है। त्याग दिया जाए. इस प्रकार देखा जाए तो पीडब्लू-7 का संस्करण जिस हद तक बी बताया गया था वह पूरी तरह से स्वीकार्य और विश्वसनीय था। [पैरा 7, 10 से 12, 15 से 17] [955-ए-बी; 956-डी-एफ; 957-डी-जी; 958-ए; 959-जी; 960-ए-बी,ई,जी; 961-ए-बी,ई-एफ]

2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, मकसद (मोटिव) बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका अस्तित्व अनुमानित तर्क की प्रक्रिया में एक ज्ञानवर्धक कारक है। इस मामले में, साक्ष्य में यह सामने आया कि आरोपी-अपीलकर्ता को मृतक और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध का संदेह था। आरोपी ने दलील दी कि उसने कभी शादी नहीं की थी। रिकॉर्ड में लाई गई सामग्रियां यह दिखाने के लिए काफी हद तक जाती हैं कि अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने समुदाय की परंपरा के अनुसार अपनी भाभी के साथ विवाह किया था, यानी 'करेवा' विवाह। साक्ष्य के उक्त पहलू पर वास्तव में हमला नहीं किया गया है या उसे हिलाया नहीं गया है। इस प्रकार, यह स्थापित हुआ कि अभियुक्त को संदेह था कि मृतक का उसके भाई की पत्नी के साथ संबंध था और इससे उसका गुस्सा भड़क गया था। उक्त मकसद ने अभियोजन के मामले को और मजबूत किया। [पैरा 18] [961-जी-962-ए-डी] सी

पडाला वीरा रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य 1989 सप्प (2) एससीसी 706; बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 सप्प (4) एससीसी 259; उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2007) 13 एससीसी 90: 2007 (13) एससीआर 653; हिमाचल प्रदेश राज्य वी. ज्ञान चंद (2001) 6 एससीसी 71: 2001 (3) एससीआर 247; यूपी राज्य वी. देवमन उपाध्याय एआईआर 1960 एससी 1125; महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू (2000) 6 एससीसी 269; जॉन पांडियन बनाम राज्य (2010) 14 एससीसी 129; कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य (2002) 6 एससीसी 81:

2002 (3) एससीआर 1; योगेन्द्र बनाम राजस्थान राज्य (2013) 12 एससीसी 399; कुंदुला बाला सुब्रमण्यम और अन्य बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (1993) 2 एससीसी 684: 1993 (2) एससीआर 666- पर भरोसा.

केस कानून संदर्भ

1989 सप्लीमेंट(2) एससीसी 706	पर भरोसा।	पैरा 7
1995 सप्लीमेंट(4) एससीसी 259	पर भरोसा।	पैरा 8
2007(13) एससीआर 653	पर भरोसा।	पैरा 9
2001(3) एससीआर 247	पर भरोसा।	पैरा 10
एआईआर 1960 एससी 1125	पर भरोसा।	पैरा 12
(2000) 6 एससीसी 269	पर भरोसा।	पैरा 13
(2010) 14 एससीसी 129	पर भरोसा।	पैरा 15
2002 (3) एससीआर 1	पर भरोसा।	पैरा 16
(2013) 12 एससीसी 399	पर भरोसा।	पैरा 17
1993 (2) एससीआर 666	पर भरोसा।	पैरा 18

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 486/2010

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, की आपराधिक अपील संख्या 770/2006 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 07.09.2009 से।

एम. एम. कश्यप, अपीलकर्ता के वकील।

प्रतिवादी की ओर से विकास शर्मा, कमल मोहन गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय, न्यायधीश दीपक मिश्रा,जे. द्वारा पारित किया गया:-

1- वर्तमान आपराधिक अपील संख्या 770-डीबी/2006 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 7.09.2009 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत डिवीजन बेंच ने दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश की पुष्टि की है। 2003 के सत्र मामले संख्या 357 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 और धारा 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उसे कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5000/- रुपये का जुर्माना और धारा 201 के तहत तीन साल का कठोर कारावास और 1000/- रुपये का जुर्माना, धारा 34 आईपीसी के साथ पढ़ें, दोनों अपराधों के संबंध में जुर्माना राशि के लिए डिफ़ॉल्ट खंड के साथ शर्त यह है कि दोनों वाक्य समवर्ती होंगे।

2. अनावश्यक विवरण के बिना, अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि सामने आया है, यह है कि 18.1.2003 को लगभग 6.30 बजे, मृतक हेत राम, आरोपी-अपीलकर्ता के साथ अपना घर छोड़ गया था और 19.1.2003 की सुबह तक वापस नहीं लौटा। 2003. मृतक के परिजनों ने उसे कई स्थानों पर तलाश किया और रिश्तेदारी में पूछताछ की लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह नहीं मिला। उस पूछताछ के दौरान एक चाय की दुकान के मालिक द्वारा यह खुलासा किया गया कि 18.01.2003 को लगभग 8.30 बजे अपीलकर्ता और मृतक ने एक साथ चाय पी थी और उसके बाद वे वहां से चले गए थे। चाय की दुकान के मालिक द्वारा सूचित किए जाने पर, मृतक का भाई सुभाष, पीडब्लू-8, पाला राम और रमेश के साथ आरोपी-अपीलकर्ता के घर गया, और उसके पिता कृष्ण कुमार, सह-अभियुक्त से जानने आया। कि राजा खारिया गांव गये थे लेकिन गांव खारिया का टेलीफोन नंबर खराब होने के कारण उनसे संपर्क नहीं हो सका. इसके बाद, मुखबिर, पीडब्लू-8, सुभाष अपने घर लौट आया और हेत राम की

वापसी के लिए रात तक इंतजार किया। जब मृतक रात तक नहीं आया, तो सुभाष अपने रिश्तेदारों के साथ फिर से अपीलकर्ता के घर गया, जो घर में मौजूद था, और उन्हें बताया कि 18.01.2003 की रात में उसने और मृतक ने एक साथ चाय पी थी, लेकिन जब वे अपने घर लौट रहे थे, एक सिख लड़का उन्हें मिला और हेत राम उस लड़के के साथ अपनी मोटर साइकिल पर चला गया। उक्त सूचना मिलने के बाद जब सूचक एवं अन्य लोग अभियुक्तों के घर से लौट रहे थे तो उन्हें मोहन एवं महेंद्र सिंह के घर के सामने गली में खून के धब्बे दिखे. इससे मुखबिर को संदेह हुआ कि उसके भाई की अपीलकर्ता ने हत्या कर दी होगी और शव को ठिकाने लगा दिया होगा। जैसा कि उल्लेख किया गया है, घटना के पीछे का मकसद यह था कि अपीलकर्ता पोस्ता की भूसी के सेवन में लिप्त था और अपीलकर्ता के पिता को संदेह था कि मृतक ने उनके बेटे को नशे की लत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपरोक्त आरोपों के आधार पर थाना रनिया में प्राथमिकी संख्या 45 दिनांक 20.1.2003 दर्ज की गयी थी. आपराधिक कानून लागू होने के बाद, जांच एजेंसी उस स्थान पर गई जहां खून के धब्बे पाए गए थे और साइट योजना तैयार की और खून से सनी मिट्टी को जब्त कर लिया। अगले दिन पुलिस जांच के सिलसिले में गांव बनी में गई तो गांव की पुरानी आबादी स्थित एक कुएं की सीढ़ियों, चबूतरे और दीवार पर खून के धब्बे मिले। पुलिस ने वहां से खून से सनी ईंटें एकत्र कीं और कुएं के अंदर एक बंडल देखा और अंततः हेत राम का शव बरामद किया जो उक्त बंडल के अंदर पाया गया था। जांच एजेंसी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल, सिरसा भेज दिया और 22.1.2003 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान अपीलकर्ता को प्रकटीकरण कथन का सामना करना पड़ा, उदाहरणार्थ। पी. ईई, इस आशय का कि वह हेत राम को झूठे बहाने से चाय की दुकान पर ले गया और उसके बाद अपने 'नोहरे' पर ले गया, जहां उसने 18.01 की रात लगभग 10.00 बजे हेत राम की गर्दन पर चाकू से वार किया था।

2003. हेत राम ने भागने की कोशिश की लेकिन उसने उसका पीछा किया और जब मृतक महेंद्र सिंह के घर के सामने गिर गया, तो उसने मृतक की छाती और कमर पर चाकू से कई वार किए। शव को अपने आंगन तक खींचकर ले जाने में असमर्थ होने के कारण उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने पिता की मदद ली। मृतक द्वारा पहना गया कंबल अपीलकर्ता के आंगन में जला दिया गया था। इसके बाद, पुलिस ने आरोपी अपीलकर्ता के बयान के आधार पर अपीलकर्ता के खून से सने कपड़े और चाकू को शौचालय के गड्ढे से बरामद कर लिया। खून से सने मिट्टी के पार्सल, आरोपी और मृतक के खून से सने कपड़े, जब्त चाकू और अन्य सामग्री को जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन भेजा गया और रिपोर्ट, एक्ज़िबिट पी.आरआर, अभियोजन पक्ष को प्राप्त हुई। जांच के दौरान, सुक्खा, पीडब्लू-7, का बयान 21.1.2003 को दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा था कि मृतक की अपीलकर्ता ने हत्या कर दी थी क्योंकि अपीलकर्ता को संदेह था कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी तरह का बयान नानक, पीडब्लू-9 ने भी दिया था। जांच अधिकारी ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी करने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। 2003 जिसमें उन्होंने कहा था कि मृतक की हत्या अपीलकर्ता ने की थी क्योंकि अपीलकर्ता को संदेह था कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी तरह का बयान नानक, पीडब्लू-9 ने भी दिया था। जांच अधिकारी ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी करने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। 2003 जिसमें उन्होंने कहा था कि मृतक की हत्या अपीलकर्ता ने की थी क्योंकि अपीलकर्ता को संदेह था कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी तरह का बयान नानक, पीडब्लू-9 ने भी दिया था। जांच अधिकारी ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी करने के बाद, आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र

दायर किया।धारा 302 और 201 आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित । सह-अभियुक्त कृष्ण कुमार पर आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 201 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सक्षम अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया। अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

3. अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए 13 गवाहों से पूछताछ की। मुख्य गवाह डॉ. एनके मित्तल, पीडब्लू-1 हैं, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, सुक्खा, पीडब्लू-7, सुभाष, पीडब्लू-8, मृतक का भाई और मुखबिर नानक हैं। पीडब्लू-9, महेंद्र, पीडब्लू-10, जिन्होंने मृतक और अपीलकर्ता को चाय की दुकान में एक साथ चाय पीते देखा था और कलावती, पीडब्लू-11, मृतक की माँ, जिसने मृतक को उनके साथ घर से निकलते देखा था। अभियुक्त-अपीलार्थी

4. आरोपी व्यक्तियों ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत अपने बयानों में आरोपों से इनकार किया और झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि आरोपी राजा की न तो किसी से शादी हुई थी और न ही वह अफीम का आदी था और इसलिए, हेत राम की हत्या करने का कथित मकसद पूरी तरह से निराधार था। उन्होंने आगे पुलिस के सामने कोई खुलासा बयान देने से इनकार किया और कहा कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सबूत बनाने के लिए लेख लगाए थे। आरोपी व्यक्तियों ने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं करने का फैसला किया।

5. विद्वान ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पूरी श्रृंखला स्थापित करने में सक्षम था

और तदनुसार अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उनके पिता ने उन्हें सजा सुनाई, जैसा कि यहां पहले कहा गया है। असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता और उसके पिता ने आपराधिक अपील दायर की थी जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की थी, लेकिन जहां तक उसके पिता कृष्ण कुमार का सवाल है, दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, कृष्ण कुमार की सजा को संशोधित कर दिया था। ट्रायल जज द्वारा लगाया गया और जुर्माने की मात्रा में हस्तक्षेप किए बिना इसे पहले ही पूरी हो चुकी अवधि तक सीमित कर दिया गया। वर्तमान अपील में राजा ने अपनी दोषसिद्धि और सजा पर आपत्ति जताई है।

6. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री एमएम कश्यप और राज्य के विद्वान वकील श्री विकास शर्मा को सुना है।

7. जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलता है, अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना पड़ता है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जा रहा है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए; वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो त्रुटिहीन रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती हों; परिस्थितियों को, संचयी रूप से लेते हुए, इतनी पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं; और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होने चाहिए और अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी भी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होने चाहिए और ऐसे साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होने चाहिए बल्कि उसकी बेगुनाही के साथ असंगत

होने चाहिए। पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य देखें। 1989 पूरक (2) एससीसी 706.

8. बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 Supp (4 एससीसी 259 में, यह निर्धारित किया गया है कि:

> "...जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और आरोपी को अपराध से जोड़ने के लिए उन परिस्थितियों को निर्णायक प्रकृति का होना चाहिए। घटनाओं की श्रृंखला में सभी कड़ियों को परे स्थापित किया जाना चाहिए एक उचित संदेह और स्थापित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी बेगुनाही के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, संदेह को अनुमति देने के खतरे से बचने के लिए अदालत को सतर्क रहना होगा कानूनी सबूत की जगह लेने के लिए और सबूत की जगह लेने के लिए भावनात्मक विचारों से प्रभावित होने के खतरे से बचने के लिए सतर्क रहना होगा, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हों।"

9. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि न्यायालय को यह देखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि घटनाओं की श्रृंखला स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से स्थापित की गई है ताकि आरोपी की बेगुनाही की किसी भी उचित संभावना को खारिज किया जा सके। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रृंखला पूरी है या नहीं, यह साक्ष्य से निकलने वाले प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर

करेगा और कभी भी किसी सार्वभौमिक मानदंड का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उज्जगर सिंह बनाम पंजाब राज्य देखें (2007) 13 एससीसी 90.

10. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित की गई परिस्थितियाँ यह हैं कि मृतक घटना की तारीख पर शाम के शुरुआती समय में आरोपी-अपीलकर्ता के साथ उसके घर से बुलाया गया था। इस संबंध में मृतक की मां कलावती, पीडब्लू-11 ने गवाही दी है। इसके बाद, रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री से यह स्पष्ट रूप से पता चला कि अपीलकर्ता को मृतक के साथ चाय की दुकान पर देखा गया था। उक्त तथ्य महेंदर, पीडब्लू द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य से, दो तथ्य स्थापित होते हैं, अर्थात्, अभियुक्त और मृतक मृतक के घर से चले गए थे और चाय की दुकान पर एक साथ चाय लेते देखे गए थे। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित अंतिम देखा गया सिद्धांत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चाय की दुकान के मालिक से पूछताछ नहीं की गई है। जब उपरोक्त दो गवाहों की गवाही स्वीकार्य होने योग्य है और रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्यों से पुष्टि प्राप्त होती है, तो चाय की दुकान के मालिक की जांच न होने के कारण कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, जैसा कि विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपीलकर्ता, एक भौतिक गवाह है। यह कानून में अच्छी तरह से तय है कि किसी महत्वपूर्ण गवाह की गैर-परीक्षा रिकॉर्ड पर उपलब्ध गवाही के वजन को कम करने का गणितीय फॉर्मूला नहीं है, अगर वह स्वाभाविक, भरोसेमंद और ठोस है [एचपी राज्य बनाम ज्ञान चंद देखें (2001)6 एससीसी 11 इसके अलावा, वह ऐसा गवाह नहीं था जो किसी तथ्य के बारे में गवाही देने के लिए अकेले सक्षम गवाह था और उसकी गैर-परीक्षा वास्तव में अभियोजन पक्ष के संस्करण को नष्ट कर देगी।

11. अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को स्वीकार करने का एक अन्य कारण यह है कि मृतक के भाई सुभाष, पीडब्लू-8 ने गवाही दी है कि उसने आरोपी से मृतक

के ठिकाने के संबंध में पूछताछ की थी, क्योंकि मृतक आरोपी के साथ गया था और उस समय आरोपी ने जवाब दिया था कि चाय की दुकान पर एक सिख लड़का आया था और मृतक उसके साथ चला गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक और आरोपी सह-ग्रामीण हैं। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में, आरोपी-अपीलकर्ता ने मृतक के साथ जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने मां, कलावती, पीडब्लू- 11, भाई, सुभाष, पीडब्लू-8 और महेंद्र, पीडब्लू-10 के साक्ष्य पर भरोसा किया है। उक्त साक्ष्यों के संचयी पढ़ने और उचित मूल्यांकन से यह बिना किसी संदेह के साबित होता है कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था।

12. एक और परिस्थिति जो साबित हो चुकी है वह चाकू, खून से सने कपड़े और जले हुए कंबल की राख की बरामदगी के बारे में है। जब्ती के गवाह सुक्खा, पीडब्लू-7 और नानक, पीडब्लू-9 ने जब्ती साबित की है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने पुलिस हिरासत में आरोपी-अपीलकर्ता का इकबालिया बयान दर्ज किया था और उसके बाद, जैसा कि आरोप लगाया गया है, बयान के लिए कुछ चीजें बरामद की थीं जो वास्तव में अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं देती हैं। पुलिस अधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया मामला अस्वीकार्य है। इसके अलावा, आरोपी ने दलील दी थी कि सामान और हथियार जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए थे। उचित परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के लिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय एआईआर 1960 एससी 1125 से एक अंश को लाभप्रद रूप से पुन: प्रस्तुत कर सकते हैं:

> " धारा 27 में, धारा 25 की तरह, अभिव्यक्ति, 'किसी अपराध का आरोपी' भी संबंधित व्यक्ति का वर्णनात्मक है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिस पर अपराध का आरोप है, धारा 27 उसके

द्वारा दिए गए कुछ बयानों को साबित करती है, जबकि वह अंदर था एक पुलिस अधिकारी की हिरासत। धारा 27 इस सिद्धांत पर स्थापित की गई है कि भले ही किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी की हिरासत में रहने के दौरान दिए गए इकबालिया बयान या अन्य बयानों से संबंधित सबूत दागदार हैं और इसलिए अस्वीकार्य हैं, यदि सत्य है उसके द्वारा दी गई जानकारी किसी तथ्य की खोज से आश्वस्त होती है, इसे बेदाग माना जा सकता है और इसलिए इसे साबित करने योग्य घोषित किया जाता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित है। हालांकि धारा 27 एक प्रावधान के रूप में है धारा 26, दोनों धाराएं आवश्यक रूप से एक ही चरित्र के साक्ष्य से संबंधित नहीं हैं। धारा 26 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध इकबालिया बयानों के सबूत के खिलाफ है। धारा 27 जानकारी के सबूत से संबंधित है चाहे वह स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं, जिससे तथ्यों की खोज होती है। धारा 27 के अनुसार, भले ही किसी तथ्य को प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजा गया माना गया हो, केवल उतनी ही जानकारी स्वीकार्य है जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित हो।"

13. महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू (2000) 6 एससीसी 259 में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के मूलभूत पहलू से निपटते समय, न्यायालय ने पाया कि उक्त प्रावधान में अंतर्निहित मूल विचार बाद की घटनाओं द्वारा स्वीकारोक्ति का सिद्धांत है, जो है इस सिद्धांत पर स्थापित किया गया है कि यदि किसी कैदी से प्राप्त किसी भी जानकारी के आधार पर की गई खोज में कोई तथ्य खोजा जाता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि कैदी द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। इसमें आगे कहा गया है

कि जानकारी प्रकृति में इकबालिया या गैर-अनुरोधात्मक हो सकती है, लेकिन अगर इसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज होती है तो यह एक विश्वसनीय जानकारी बन जाती है और इसलिए, विधायिका ने स्वीकार्य हिस्से को सीमित करके ऐसी जानकारी को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी है। न्यूनतम।

14. इस प्रकार, यदि कोई आरोपी व्यक्ति ऐसा बयान देता है जो उससे प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज से संबंधित है तो वह स्वीकार्य है। कथन के शेष भाग को अस्वीकार्य माना जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त-अपीलकर्ता के कहने पर की गई वसूली को ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी सही माना है और हमें इसमें कोई दोष नहीं लगता है।

15. एक अन्य परिस्थिति जिस पर उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया है वह यह है कि खून से सने कपड़े और हथियार, चाकू को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कपड़े व चाकू पर खून के धब्बे पाये गये हैं. यह सच है कि ब्लड ग्रुप का मिलान नहीं हुआ है. हालाँकि, इससे वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरोपी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कपड़े और चाकू पर मानव खून कैसे लगा। इस संबंध में, जॉन पांडियन बनाम राज्य (2010) 14 एससीसी 129 का एक अंश पुन: प्रस्तुत करने लायक है:

> "खोज विश्वसनीय प्रतीत होती है। इसे नीचे की दोनों अदालतों ने स्वीकार कर लिया है और हमें इसे खारिज करने का कोई कारण नहीं मिलता है। यह इस तथ्य से अलग है [तस्वीर] कि यह हथियार फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) को भेजा गया था और यह मानव रक्त से सना हुआ पाया गया है। हालांकि रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सका, क्योंकि परिणाम अनिर्णायक थे, आरोपी को

कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ा कि इस हथियार पर मानव रक्त कैसे आया। उसने कुछ नहीं दिया। यह खोज बहुत सकारात्मक होगी अभियोजन मामले को आगे बढ़ाएं।"

उपरोक्त के मद्देनजर, अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी को स्वीकार न करने का कोई ठोस कारण नहीं है। यहां यह भी नोट करना उचित है कि डॉ. एनके मित्तल, पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से राय दी है कि मृतक के शरीर पर चोटें चाकू के कारण हो सकती हैं और उक्त राय का खंडन नहीं किया गया है।

16. एक अन्य परिस्थिति जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि सुक्खा, पीडब्लू-7, एक टैक्सी चालक ने गवाही दी है कि 18.1.2003 को लगभग 11.00 बजे जब वह यात्रियों को लेने के लिए फतेहाबाद जा रहा था, तो उसने सामने एक बैलगाड़ी खड़ी देखी। आरोपी के घर और कुछ लोग "पल्ली" में एक बंडल बांध रहे थे। उसके पूछताछ करने पर आरोपियों ने उसे बताया कि वे खेतों में खाद ले जा रहे हैं। हालाँकि, इस गवाह ने अतिशयोक्तिपूर्ण बयान दिया है और गिरफ्तारी के समय के बारे में अलग-अलग बताया है, फिर भी इस आशय की उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि उसने आरोपी को एक विशेष स्थान पर "पल्ली" में एक बंडल के साथ देखा था। कहावत "फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ऑम्निबस", भारत में लागू नहीं है। कृष्णा मोची बनाम बिहार राज्य (2002) 6 एससीसी 81 में, इसे इस प्रकार आयोजित किया गया है:

"फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ऑम्निबस" की कहावत का भारत में कोई उपयोग नहीं है और गवाहों को झूठा करार नहीं दिया जा सकता। "फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ऑम्निबस" (एक बात में झूठ, हर चीज में झूठ) वाली कहावत को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है। न

ही यह कहावत कानून के शासन का दर्जा प्राप्त कर पाई है। यह केवल सावधानी का नियम है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों में गवाही की उपेक्षा की जा सकती है, न कि यह कि इसकी अवहेलना की जानी चाहिए।"

17. योगेन्द्र बनाम राजस्थान राज्य (2013) 12 एससीसी 399 में, यह फैसला सुनाया गया है कि न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि गवाह की गवाही पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। अदालत को झूठ को सच से अलग करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और यह केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए, जब अनाज को भूसी से अलग करना पूरी तरह से असंभव हो, क्योंकि ये दोनों चीजें इतनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं कि इस तरह के पूरे सबूत गवाह को खारिज कर देना चाहिए. इस प्रकार देखा जाए तो पीडब्लू-7 का संस्करण जिस हद तक यहां ऊपर बताया गया है वह पूरी तरह से स्वीकार्य और विश्वसनीय है।

18. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, मकसद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसका अस्तित्व अनुमानित तर्क की प्रक्रिया में एक ज्ञानवर्धक कारक है [कुंडु ला बाला सुब्रमण्यम और अन्य देखें। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य(1993) 2 एससीसी 684। इस मामले में साक्ष्यों में यह बात सामने आई थी कि आरोपी-अपीलकर्ता को मृतक और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध का संदेह था। आरोपी ने दलील दी है कि उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। यह उल्लेखनीय है कि रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री यह दिखाने के लिए काफी हद तक जाती है कि अपने भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने समुदाय की परंपरा के अनुसार अपनी भाभी के साथ विवाह किया था, यानी 'करेवा' विवाह। साक्ष्य के उक्त पहलू पर वास्तव में हमला नहीं किया गया है या उसे हिलाया नहीं गया है। इस प्रकार, यह स्थापित हो गया है कि आरोपी को संदेह था कि मृतक

का उसके भाई की पत्नी के साथ संबंध था और इससे उसका गुस्सा भड़क गया था। उक्त मकसद अभियोजन के मामले को और मजबूत करता है।

19. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील पूरी तरह से योग्यता से रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **देविका गुजराल** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।